

दिनांक

आज्ञा पत्र

19.02.2025

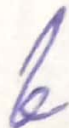
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं० 1 लगायत 4 बावजूद रजिस्टर्ड तामील हाजिर नहीं आए इसलिए इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। बहस प्रार्थना-पत्र टी०आई० सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा०का०अधिनियम में अंकित प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि आवेदक एवं अनावेदकगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। कृषि भूमि अंतर्गत खाता सं० 472 नया 453 पुराना ख०नं० 1420 रकबा 0.6400 है० ग्राम शिशू तहसील दांतरामगढ़, सीकर में स्थित है। इसमें आवेदक का हिस्सा 1/2, अनावेदक सं० 1 का हिस्सा 3/64, अनावेदक सं० 02 का हिस्सा 1/4, अनावेदक सं० 3 का हिस्सा 13/64 निहित है। आवेदक व अनावेदक सं० 1 ता 3 की वर्णित भूमियां पुश्तैनी हैं। पक्षकारान के मध्य आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इस कारण पक्षकारान उक्त भूमियों में संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। पक्षकारान के मध्य उक्त भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण आवेदक को अपने हक हिस्से की भूमियों को समुचित रूप से विकसित करने में असक्षम है। आवेदक उक्त भूमियों में काश्त कर अपना व परिवार का पालन करता है। अनावेदक सं० 1 ता 3 जो कि झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वे आये दिन प्रार्थी को हैरान परेशान करते हैं तथा भूमियों में काश्त कार्य करने से अनावश्यक रूप से हैरान व परेशान कर प्रार्थी से झगड़ा करने पर आमादा रहते हैं। आवेदक द्वारा अनावेदक सं० 1 ता 3 को भूमियों का विधिवत बाई मिट्स एंड बाउण्डस विभाजन करने हेतु कहा तो आवेदक को अनर्गल कथन कर समय निकाला जाकर बंटवारा नहीं किया जा रहा है। इस कारण आवेदक को माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। आवेदक ने आवेदन पत्र अं० धारा 212 रा०का०अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थी सं० 1 ता 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया है।

चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण वाद के गुणावगुण व मेरिट के आधार पर होना है। अप्रार्थी सं० 1 ता 4 बावजूद रजिस्टर्ड तलबी के उपस्थित नहीं आए हैं। पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े तथा मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

कलक्टर(मु०)सीकर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि ख०नं० 1420 रकबा 0.6400 है० ग्राम शिशू प०ह० शिशू भू०अ०नि० रानोली तहसील दांतारामगढ़, सीकर में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फौशल शुमार होकर नंबर से कम हो।


सहायक कलक्टर (मु०)सीकर